क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

E-mail: krantisamay@gmail.com
संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 184, शनिवार, 28 जुलाई, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमित शाह से मिलने सुरक्षा घेरा तोड़ एयरपोर्ट में घुसे भाजपाई, तोड़ा शीशा

इलाहाबाद (एजेंसी)। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के लिए कई भाजपा कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। एयरपोर्ट लॉबी के गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने रोका तो वहां भी तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गई। गेट पर धक्कामुक्की में लॉबी गेट का शीशा टूट गया। सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आपा खो बैठे और शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटने के बाद सुरक्षाकर्मी सख्त हुए और जबरन घुसे कार्यकर्ताओं को लॉबी में जाने नहीं दिया। इस घटना की जानकारी होने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नाराज हुए और कार्यकर्ताओं को खरी-खोटी सुनाई। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष के एयरपोर्ट पर स्वागत को लेकर विवाद हो गया। स्वागत के लिए 39 नेताओं की सूची तैयार की गई थी। इस लिस्ट में सांसद श्यामाचरण गुप्त, विनोद सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह और विधायक नीलम करवरिया का नाम नहीं था। एयरपोर्ट रनवे के गेट पर रोके जाने के बाद सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक भड़क गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाम नहीं होने पर जनप्रतिनिधि भड़के और अंदर रनवे पर घुस गए। भाजपा अध्यक्ष विमान से उतरने के बाद सभी से मिले और लगभग 15 मिनट के लिए रुक गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा पर विधायक नीलम करवरिया ने पार्टी के एक पदाधिकारी को खरी-खोटी सुनाई। एयरपोर्ट के अंदर गए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई। स्वागत करने वालों की लिस्ट में जनप्रतिनिधियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर ऐसे लोगों का नाम था जो पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़ते।

उप मुख्यमंत्री के पीछे घुसे कार्यकर्ता

इलाहाबाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार सुबह 8.35 बजे एयरपोर्ट के गेट पहुंचे। एयरपोर्ट के गेट पर उप मुख्यमंत्री पांच मिनट रुके। उप मुख्यमंत्री की गाड़ी एयरपोर्ट परिसर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी तो बैरीकेडिंग हटाई गई। उप मुख्यमंत्री की गाड़ी के पीछे पार्टी के लगभग दो दर्जन कार्यकर्ता एयरपोर्ट परिसर में घुस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की लिस्ट में जिनका नाम नहीं था वो बड़े नेताओं की गाड़ी में अंदर गए।

अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ाती रहीं शशि

इलाहाबाद। बम्हरौली एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत करने से भाजपा की पूर्व महानगर अध्यक्ष शशि वार्ष्णेय वंचित रह गईं। शशि वार्ष्णेय का नाम स्वागत करने वालों की लिस्ट में नहीं था। वरिष्ठ भाजपा नेता एक घंटे तक एयरपोर्ट के गेट पर सुरक्षाकर्मियों से अंदर जाने देने के लिए गिड़गिड़ाती रहीं। एयरपोर्ट के अंदर जाने को नहीं मिला तो शशि वहां ले लौट पड़ीं।

यूपी : मॉब लिंचिंग रोकने को जिलों में बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स

लखनऊ (एजेंसी)। डीजीपी ओपी सिंह ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा एवं हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए सभी पुलिस कप्तानों को नोडल अधिकारी नामित किया है। इसके साथ ही उन्हें इस कार्य के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं जघन्य अपराध हैं। गलत अवधारणाओं के आधार पर व्यक्तियों के किसी समूह अथवा भीड़ द्वारा कानून का स्वयं पालन कराए जाने के नाम पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई करना कानून के तहत पूर्णतया अक्षम्य एवं दण्डनीय अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 के अपने एक फैसले में मॉब लिंचिंग की रोकथाम एवं ऐसी घटनाओं की विवेचनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा है कि जिलों में नोडल अधिकारी की सहायता के लिए सभी जिलों में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के एक अधिकारी होंगे, जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

दुनिया की हर बेहतर सुविधाएं यूपी को देंगे : सुरेश खन्ना

लखनऊ। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को दुनिया में मिलने वाली सभी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी। देश के अन्य राज्यों में जो भी बेहतर काम हुआ है उसे भी यूपी में शुरू किया जाएगा। आय बढ़ाने के लिए लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम बांड जारी करेंगे।

नगर विकास मंत्री स्मार्ट सिटी, अमृत व प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को आयोजित उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी, अमृत व प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं। इन योजनाओं में हम कहां पहुंचे इस पर विचार करना होगा। वर्ष 2015 में जब ये योजनाएं लांच हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। उस समय ने इन योजनाओं पर ठीक से काम नहीं किया।

उनकी सरकार बनने के बाद इन योजनाओं में तेजी आई है। अमृत योजना में 6500 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों में दो लाख से अधिक घरों में पानी व सीवर का कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है।

स्मार्ट में चुने गए 10 शहरों में बेहतर काम चल रहा है।

शहरों को बेहतर स्ट्रीट लाइट की सुविधा देने के लिए 6.50 लाख एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ व झारखंड ने बेहतर काम किए हैं। इससे हमे सीखने की जरूरत है।

पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अधिकारी ने बचाई थी जान

करगिल युद्ध के एकमात्र युद्धबंदी थे नचिकेता

भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़े गए युद्ध को जीतने की याद में प्रत्येक साल 26 जुलाई को करिगल विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत ने दोबारा अपने उन दुर्गम स्थानों पर कब्जा हासिल किया जिसपर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। करगिल की लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया था जो 60 दिनों से ज्यादा चली थी और 26 जुलाई को खत्म हुई थी। करगिल विजय दिवस करगिल के द्रास सेक्टर और नई दिल्ली में मनाया जाता है जहां प्रधानंमत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं देशभर में कई स्थानों पर इससे जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। करगिल युद्ध के दौरान 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे।

जोधपुर ■ एजेंसी

देश आज भारतीय सेना के जवानों के साहस, वीरता और जज्बे के दम पर करगिल युद्ध को फतह करने की खुशी में विजय दिवस मना रहा है। दो माह लम्बे इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता इकलौते ऐसे सैनिक थे जिन्हें युद्धबंदी बनाया गया। लेकिन, पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अधिकारी ने उनकी जान बचाई। आठ दिन तक काफी टॉर्चर करने के बाद उन्हें फिर से भारत को सौंपा गया।

- 26 वर्षीय फाइटर पायलट नचिकेता को करगिल में 17 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मिग-27 से उड़ान भर उन्होंने अपने एक लक्ष्य पर निशाना साधा ही था कि एक मिसाइल उनके विमान से टकराई और इंजन में आग लग गई। कमर के बल जमीन पर गिरने के कारण वे घायल हो गए। थोड़ी देर में पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया।
- **पाकिस्तानी सैनिकों ने घेराः** 10 साल बाद नचिकेता ने हादसे से जड़े किस्से सुनाए। उन्होंने कहा कि नीचे गिरने के आधा घंटे बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपनी पिस्टल से छह राउंड फायर किए। पाकिस्तानी सैनिकों ने भी उन पर फायर किए, लेकिन वे खुशकिस्मत रहे कि एक भी गोली उन्हें नहीं लगी।
- इस बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ते ही उन्होंने नचिकेता के साथ मारपीट शुरू कर दी। नचिकेता को बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। कैसर ने अपने उग्र सैनिकों को मुश्किल से काबू कर नचिकेता को अपने साथ एक कमरे में ले गए।
- नचिकेता बताते हैं कि- कैसर ने दोस्ताना व्यवहार किया। मेरे परिवार और एयर फोर्स से जुड़ने की बातें की। बाद में कैसर ने कहा भी उनके और नचिकेता के व्यक्तिगत जीवन में बहुत समानताएं मिलीं। इस कारण वे नचिकेता से प्रभावित हुए।
- वहां से नचिकेता को बटालिक सेक्टर में किसी स्थान पर ले जाया गया। बाद में एक हेलीकॉप्टर से स्कार्दू। वहां उन्हें लगातार टॉर्चर कर पूछताछ की गई। नचिकेता ने कहा भी था कि हर वक्त मौत सामने नजर आती थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि एक दिन अवश्य वे भारत वापस लौट सकेंगे।

करगिल के 5 हीरो, जिन्हें आप नहीं जानते

करगिल की लड़ाई को 19 साल हो गए। 26 जुलाई 1999 वह दिन था जब पाकिस्तान ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। सीमा पर हमले की शुरुआत करने वाले पाक के पास भारत के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। भारतीय जवानों के साहस, वीरता और जज्बे के सामने पड़ोसी मुल्क की सेना हार मान चुकी थी। करीब दो महीने तक चलने वाले इस युद्ध में जीत मिलने के साथ ही दुनिया को भारत की ताकत का सबूत भी देखने को मिला। सरकारी आंकड़ों में करीब 527 देश के जवान शहीद हुए और करीब 1,300 से ज्यादा योद्धा घायल हुए थे। आइए जानें, इस लड़ाई का हिस्सा बने दिल्ली-हृष्टक्के जांबाज वीरों की कहानियां...

पाकिस्तान से जीत छीन ले आए ये परमवीर

करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी फौज की फतह की यादगार है। उसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने करगिल को पाकिस्तानी फौज से आजाद कराया और अपनी सरजमीं पर तिरंगा लहराया था। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली विजय के पीछे कई शहीदों ने देश के लिए बलिदान दिया था। आगे की स्लाइड्स में जानें उन परमवीरों के बारे में जिनके दम पर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर तिरंगा लहराया था...

विक्रम बत्रा

शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को करगिल युद्ध में उनकी अविस्मरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा था कि, %या तो मैं तिरंगे को लहराकर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटकर। लेकिन मैं आऊंगा जरूर।% दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पर भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कठिन माने जाने वाले ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे।

योगेंद्र सिंह यादव

उन्हें करगिल युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था। यह सम्मान दिए जाते समय उनकी उम्र महज 19 साल थी। परमवीर चक्र पाने वाले वह सबसे युवा सैनिक हैं। योगेंद्र का जन्म बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहिर गांव में 10 मई 1980 को हुआ। उनके पिता करण सिंह यादव सेना की कुमांऊ रेजिमेंट में थे। उन्होंने देश की ओर से 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध में हिस्सा लिया था।

रायफलमैन संजय कुमार

संजय कुमार को उनकी वीरता और अप्रतिम शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुआ। उन्होंने 3 बार सेना में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका आवेदन स्वीकार नहीं हो पाता था। चौथी बार आवेदन करने पर उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। करगिल युद्ध में गोली लगने के कारण उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पाकिस्तानी सैनिक की मशीन गन उठाई और दुश्मन के बंकर में घुस गए। हाथ से लड़ते हुए उन्होंने 3 दुश्मनों को मार गिराया।

मनोज कुमार पाण्डेय

कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय महज 24 साल की उम्र में करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। वह गोरखा राइफल्स में थे। गोरखा रायफल्स अपनी वीरता और निडरता के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। मनोज को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

हवलदार चुनी लाल

हवलदार चुनीलाल जम्मू एंड कश्मीर पैदल सेना की 8वीं बटालियन के सैनिक थे। उनका जन्म जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में हुआ। करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने उन्हें वीर चक्र और सेना पदक से सम्मानित किया।

यमुना की सफाई पर एनजीटी ने की निगरानी समिति गठित

डीएमआरसी के अवैध बोरवेल सील होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बृहस्पतिवार को यमुना नदी की सफाई के संबंध में एक निगरानी समिति गठित की और उसे इस मुद्दे पर एक कार्य योजना सौंपने का निर्देश दिया।

एनजीटी प्रमुख एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेवानिवृत्त विशेषज्ञ सदस्य बीएस सजवान और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा को समिति का सदस्य बनाकर उन्हें सितंबर तक कार्य योजना तथा 31 दिसम्बर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। एनजीटी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों से यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए समिति की मदद करने को कहा। एनजीटी ने अधिकारियों को यमुना डूब क्षेत्र पर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड को 30 जुलाई को बैठक करके यमुना सफाई कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत आने वाले एक नाले पर सीवेज शोधन संयंत्र लगाने के लिए भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड को यमुना की सफाई को लेकर आड़े हाथ लिया था और कहा था कि बीते तीन वर्ष में जमीन पर कोई ''खास प्रगति' नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि 14 सीवेज शोधन संयंत्रों पर काम शुरू तक नहीं हुआ है। अदालत के 13 जनवरी 2015 के फैसले के अनुसार इनका काम मार्च 2017 तक पूरा होना था।

भूजल दोहन को गंभीर मुद्दा बताते हुए एनजीटी ने दिया सील करने का आदेश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में भूजल दोहन को बहुत ही गंभीर मुद्दा बताते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के गैरकानूनी रूप से चल रहे बोरवेलों को सील करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को दिल्ली की ओर से पेश वकील ने बताया कि डीएमआरसी को पूरे शहर में केवल 164 बोरवेल के लिए अनुमति दी गई थी और उसे इससे अधिक बोरवेल के लिए मंजूरी की जरूरत है जिसके लिए मामला प्रक्रिया में है। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि डीएमआरसी को केवल उन बोरवेल के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए जिनके लिए कानून के अनुरूप अनुमति मिली हुई है। पीठ ने कहा है कि पक्षों के वकीलों को सुनने और इस बात पर विचार करने के बाद कि एनसीटी दिल्ली में भूजल का दोहन बहुत गंभीर मुद्दा है, केवल उन बोरवेल के संचालन की अनुमति होगी जिन्हें कानून के अनुरूप मंजूरी मिली हुई है। पीठ ने कहा है कि इसलिए हम निर्देश देते हैं कि एनसीटी दिल्ली द्वारा जिन बोरवेल की मंजूरी प्राप्त की गई है केवल उन्हें ही चलने दिया जाए। अन्य सभी बोरवेल सील किये जाएं।

अधिकरण ने डीएमआरसी को अन्य बोरवेल के लिए अनुमति मिल जाने पर उनके लिये नया आदेश प्राप्त करने के लिये उसके पास आने की छूट प्रदान की। अधिकरण ने कुश कालरा की याचिका पर यह आदेश दिया। यचिका में लगाया था कि डीएमआरसी ट्रेनों की धुलाई के लिए शोधित जल के बजाय भूजल का दोहन कर रहा है।

जिससे भूजल स्तर में कमी आ रही है। अधिवक्ता कुश शर्मा के जरिये दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि डीएमआरसी ने अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध बोरवेल लगा रखे हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

युवक कांग्रेस का प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूथ कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितता, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संसद घेराव का आह्वान किया था। संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रायसीना मार्ग पर रोक लिया। भारी संख्या में जमा हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने में रखा। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। प्रदर्शन की वजह से जंतर-मंतर, रायसीना रोड, अशोक मार्ग व संसद मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गयी। प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव ने किया।

युवक कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद यादव ने कहा कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा युवा परेशान है। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर युवाओं को ठगा गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस सरकार में युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। यादव ने कहा कि युवाओं से हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। अब युवाओं का सामना करने से मोदी सरकार भयभीत है।

ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है, शौर्य का वाक संयम, ज्ञान का शांति और विनय तथा सार्मय का आभूषण क्षमा है -भतृहरि

मौत भयानक त्रासदी

राजधानी दिल्ली में रिक्शाचालक पिता मंगल की तीन बच्चियां आठ साल की शिखा, चार साल की मानसी और दो साल की पारूल गरीबी, कुपोषण और भूख के कारण मौत की नींद सो गई। भूख से इन तीनों बच्चियों की मौत भयानक त्रासदी है। इससे महज सरकारी और प्रशासनिक तंत्र की विफलता कहकर अपनी आंखें नहीं मूंदी जा सकती। वास्तव में यह सामाजिक मूल्यों के क्षरण का प्रतीक है। इसके बारे में समाजशास्त्रियों को विचार-विमर्श करने की जरूरत है। उदारीकरण और बाजारवाद ने जिन मूल्यों को जन्म दिया है और जिस तरह की स्वार्थी और क्रूर समाज की निर्मिति हो रही है, शायद उसी की यह परिणति है। पिछले कुछ वर्षो से इस तरह की पाशविक-सामाजिक प्रवृत्ति तेजी से विकसित हुई है। स्वस्थ सामाजिक संरचना में अपने पड़ोसियों की भी दुख-दर्द का ख्याल रखा जाता है। इसे ही सामुदायिक भावना कहते हैं। किसी भी संकटग्रस्त परिवार की मदद के लिए पूरा समाज आगे आकर खड़ा हो जाता है। दया और करुणा जैसे सामाजिक मूल्य ही स्वस्थ समाज का चरित्र है। इन्हीं गुणों और मूल्यों के कारण दिव्यांग और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की मदद करते हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में रहने वाला मंगल इन दिनों बेरोजगार हो गया था। लुटेरों ने उसका रिक्शा लूट लिया था। बेरोजगारी के कारण मकान भाड़ा देने की बात तो दूर थी, वह दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। यह जानते हुए भी कि मंगल बेरोजगार है, मकान-मालिक ने भाड़ा न चुकाने के कारण उसे परिवार सहित घर से बाहर निकाल दिया था। यह क्रूरता की हद है। यह बहुत डरावनी स्थिति है और इसपर समाजसेवी संगठनों को भी आगे आकर सामाजिक विफलता के कारणों को समझने और समझाने की जरूरत है। लेकिन जैसा आमतौर पर होता रहा है, इस भयानक त्रासदी को लेकर सियासी दल रोटियां सेंकने लगे हैं। दिल्ली प्रदेश में राजनीति करने वाले नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या नेता इस त्रासदी के कारणों की गहराई से पड़ताल कर पाएंगे? वास्तव में इस त्रासदी को सामाजिक विफ लता के रूप में देखने की जरूरत है।

बैंकों को करोड़ों की चपत

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 संसद द्वारा पारित किया जाना निश्चय ही महत्वपूर्ण है। बैंकों को करोड़ों की चपत लगाकर विदेश भागने वालों को लेकर देश में काफी समय से हंगामा मचा हुआ है। हालांकि ऐसे कानून पहले से हैं, जिनसे ऐसे लोगों से धन वसूलने के लिए कार्रवाई की जा सकती हैं। पर ये पर्याप्त नहीं हैं। आज की स्थिति में जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो बैंकों की पहुंच एवं न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर भाग रहे हैं, इसके लिए विशिष्ट कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

मोदी सरकार ने पहले इसे अध्यादेश के रूप में क्रियान्वित किया और अब संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया। जो माहौल है, उसमें कोई पार्टी इसका विरोध कर नहीं सकती थी। इसके पारित होने पर कोई संदेह नहीं था। इसका मूल उद्देश्य ऐसे वित्तीय अपराधियों को वापस लाकर सजा देना, बैंकों की राशि वसूलना तथा संभावित भगोड़ों को रोकना है। दोनों प्रकार के प्रावधान इसमें हैं। इसके बाद मामला सामने आने के साथ ही ऐसे ज्यादातर आरोपियों को देश से बाहर जाने से रोका जा सकता है। कानून के अमल में आने के साथ न केवल ऐसे भगोड़ों की संपत्ति जब्त होगी बल्कि उन्हें स्वदेश लाना आसान होगा।

भगोड़ों की अनुपस्थिति के कारण न्यायालयों के लिए भी समस्या हो जाती है। कहने की जरूरत नहीं कि जब आरोपी उपस्थित ही नहीं होगा तो उसकी जांच सही तरीके से नहीं हो सकती। न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पैदा होती है तथा न्यायालय का मूल्यवान समय बरबाद होता है। बैंकों से भारी राशि निकल जाने के कारण उनकी वित्तीय हालत भी खराब होती है। अब कानून की ताकत हाथ में आने के बाद जांच एजेंसियों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब आरोपियों की संपत्ति आसानी से जब्त हो सकती है। कानूनों का एक भयनिवारक प्रभाव होता है। ऐसे कानून भी वित्तीय गबन करके विदेश भागने की मंशा रखने वालों को भयभीत करेंगे कि हमें चाहे जहां चले जाएं, हमारी खैर नहीं।

छिटपुट हिंसा और एकाध आतंकी घटना

रुझानों के अनुसार इमरान खान की पीटीआई ने नेशनल असेंबली की 119 सीटों पर अजेय बढ़त बना ली है, वहीं नवाज शरीफकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को मात्र 63 सीटें मिलती दिख रही हैं। आसिफअली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) 38 सीटों पर सिमटती लग रही है। पांच धार्मिक राजनीतिक दलों के गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) को केवल 9 सीटों पर बढ़त हासिल है। अन्य छोटे-मोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार 50 से अधिक सीटों पर दबदबा बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ़ खान अब्दुल गफ्फार

सतीश पेडणोकर

पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया सहित विश्व के अनेक देशों की निगाहें पाकिस्तान के आम चुनाव पर टिकी थीं। बीती 25 जुलाई को छिटपुट हिंसा और एकाध आतंकी घटना के बीच संपन्न चुनाव ने देश के राजनीतिक हलकों में नया तूफान ला दिया है। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ(पीटीआई) बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि 270 सीटों पर हुए चुनाव में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन को 137 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। रुझानों के अनुसार इमरान खान की पीटीआई ने नेशनल असेंबली की 119 सीटों पर अजेय बढ़त बना ली है, वहीं नवाज शरीफकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को मात्र 63 सीटें मिलती दिख रही हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) 38 सीटों पर सिमटती लग रही है। पांच धार्मिक राजनीतिक दलों के गठबंधन मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) को केवल 9 सीटों पर बढ़त हासिल है। अन्य छोटे-मोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार 50 से अधिक सीटों पर दबदबा बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ़ खान अब्दुल गफ्फार खान के वंशज और आवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफ्संदयार खान और ख्वाजा आसिफ सहित देश के कई बड़े नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की गलियों और सड़कों को मिनटों में लोगों के हुजूम से भर देने और किसी भी सरकार को अपने घुटने पर आने के लिए विवश कर देने वाले धार्मिक, राजनीतिक और अतिवादी दलों के बड़े नेताओं, जिनमें सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान और अहमद लुधियानवी शामिल हैं, को करारी शिकस्त मिली है। देश के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलों-पीएमएल-एन, पीपीपी, एएनपी और एमएमए-ने परिणामों को ''सिस्टेमैटिक मैनीपुलेशन' करार देते हुए खारिज कर दिया है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहबाज खान ने बुधवार देर रात एक प्रेस कांफ्रेंस में नतीजों पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए इन्हें खारिज कर दिया। यह आरोप भी लगाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में फार्म-45 (जिसमें डाले गए कुल वोटों और सही पाए गए वोटों की जानकारी दर्ज होती है) उनके पोलिंग एजेंटों को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा उन्हें मतगणना स्थल से भी बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इस बात से इनकार किया है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक संपन्न हुए आम चुनावों में, कई कारणों से, यह राजनीतिक रूप सर्वाधिक उथल-पुथल वाला चुनाव रहा। तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ़ जिन्हें पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने अयोग्य घोषित कर दिया था, को हाल ही में नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने वतन वापसी की और जेल जाना स्वीकार किया। नवाज द्वारा चुनाव में भाग न ले पाने का खमियाजा उनकी पार्टी को से भुगतना ही था। हालांकि एक सवाल जिसका जवाब जानने की पाकिस्तानी मीडिया में बहुत कम या न के बराबर कोशिश हो रही है, वह है वहां की सेना और इंटेलीजेंस एजेंसियों की चुनाव-पूर्व, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद की भूमिका! पाकिस्तान की राजनीति पर लगातार नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना, जिसे किसी भी लोकप्रिय नेता का उभरना और राजनीति के शीर्ष पर बने रहना कतई पसंद नहीं है, ने परदे के पीछे से पी.टी.आई की होने वाली जीत में सर्वाधिक अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि कई विश्लेषकों ने चुनाव होने से पूर्व ही कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान में अगले प्रधानमंत्री का सेलेक्शन तो हो गया है, लेकिन उसको वैध बनाने के लिए इलेक्शन कराए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर वैंकि कसना शुरू कर दिया था। अब चूंकि पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की शक्ति को संविधान संशोधन द्वारा हटा देने की स्वीकृति पहले ही दे दी थी, इसलिए सेना को नवाज को हटाने के लिए देश की न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जिस आधार पर देश की सर्वोच्च अदालत ने नवाज को बेदखल किया था, उसके आधार पर किसी भी राजनेता का राजनीतिक भविष्य खत्म किया जा सकता है। नवाज को चुनाव की प्रक्रिया से हटाने के बाद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी ताकत झोंककर पी.एम.एल.-एन. और पी.पी.पी. के ऐसे नेताओं पर दबाव बनाना शुरू किया जो

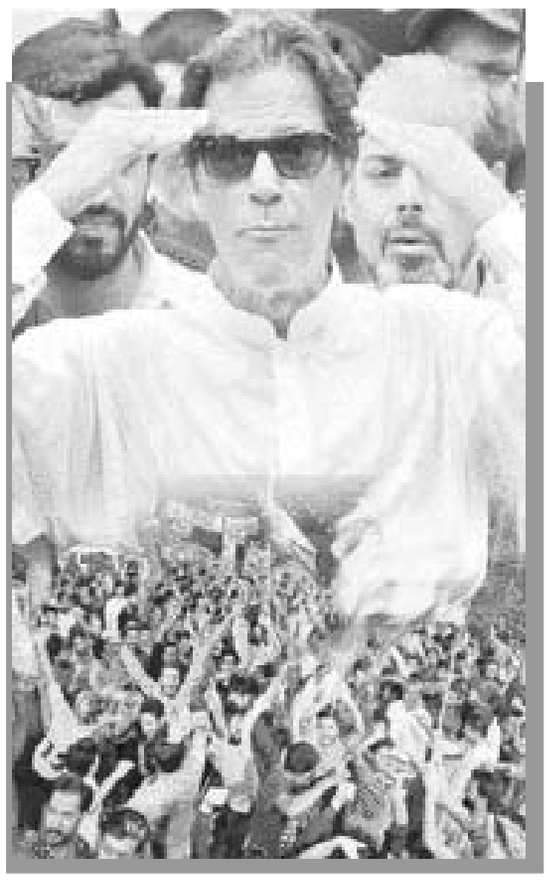

अपने दम पर भी चुनाव जीत सकते थे। इनमें अधिकतर ने या तो पी.टी.आई. के टिकट पर यह चुनाव लड़ा या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। कुछ ने तो उस समय पी.एम.एल.-एन. का साथ छोड़ा जब उनके चुनाव पी.एम.एल.-एन. के टिकट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी थी। यही कारण है कि चुनाव में जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या 50 के आकड़े को छू रही है। जो बची-खुची कसर थी वो चुनाव में सेना की भारी तैनाती और अनियमितता ने पूरी कर दी। इन सबका परिणाम हुआ कि देश की राजनीति में अब तक रहे आधार स्तंभ अपने आपको लड़खड़ाने से नहीं बचा पाए। इमरान खान का पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाना अब मात्र औपचारिकता है। देखना यह है कि वो अपनी भूमिका का निर्वाह किस तरह से करते हैं। दक्षिण एशिया खासकर भारत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की विदेश नीति किस करवट बैठेगी? क्या पाकिस्तान अभी भी अफगानिस्तान और भारत के प्रति अपना पुराना रवैया अपनाएगा और आतंकियों की शरण गाह बना रहेगा? अमेरिका के साथ संबंधों में बढ़ती दूरी और चीन से होती निकटता का क्रम जारी रहेगा? वैसे तो इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्त में छिपे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और इंटेलीजेंस एजेंसियों ने चुनाव में भूमिका निभाई है, वह उत्पन्न परिस्थितियों का पूरा-पूरा फ ायदा उठाने का प्रयास भी करेगी। अत: भारत के नीति-निर्माताओं को चाहिए कि अपनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नीति में न केवल आवश्यक परिवर्तन करें बल्कि आने वाली परिस्थितियों का सही आकलन करते हुए उनसे सफलतापूर्वक निपटने की तैयारी भी पूरी कर लें।

चलते चलते

''टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस'

किसी महिला पर यौन हमले के बाद सड़क पर प्रतिरोध के स्वर आरोपितों के खिलाफ मुखर हो उठती हैं। मगर मुजफ्फरपुर (बिहार) के बालिका गृह में एक नहीं 29 बच्चियों के साथ हो रहे लगातार यौन शोषण बिहार सरकार द्वारा संचालित बालिका गृह में यौन शोषण की शिकयतों के बाद राज्य सरकार ने ''टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस' को ऑडिट का काम दिया था।

निर्भया कांड के बाद भारतीय समाज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ज्यादा संजीदा हुआ है। किसी महिला पर यौन हमले के बाद सड़क पर प्रतिरोध के स्वर आरोपितों के खिलाफ मुखर हो उठती हैं। मगर मुजफ्फरपुर (बिहार) के बालिका गृह में एक नहीं 29 बच्चियों के साथ हो रहे लगातार यौन शोषण और बलात्कार के खुलासे के बाद भी कहीं कोई उत्तेजना का भाव नहीं दिखना क्षोभ पैदा करता है। मालूम हो कि बिहार सरकार द्वारा संचालित बालिका गृह में यौन शोषण की शिकयतों के बाद राज्य सरकार ने ''टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस' को ऑडिट का काम दिया था। संस्थान ने 7 महीने में राज्य के 38 जिलों के 110 संस्थानों का सर्वेक्षण करने के बाद 23 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद 10 लोगों गिरफ्तार किया गया। मगर इस मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को पुलिस द्वारा रिमांड पर नहीं लिया जाना और जांच में राज्य की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा का नाम आना एक नापाक गठजोड़ की इशारा करता है। गठजोड़ कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जो कमिटी इन बालिका गृह के लिए बनी हुई है उसमें दर्जन भर लोग हैं। मगर किसी ने कुछ नहीं देखा-सुना। इसके अलावा राज्य विधिक आयोग और स्थानीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की भी निगरानी की जिम्मेदारी थी। बेहतर होगा की स्वतंत्र आयोग की निगरानी में मामले की समयबद्ध जांच हो। बॉबी और शिल्पी-गौतम हत्याकांड बिहार में सत्ता के रसूख का कड़वा अतीत है, जब आरोपितों का बाल भी बांका नहीं हुआ था। 1983 के बॉबी मामले में तो जगन्नाथ मिश्र की सरकार पर बन आई थी। ताजा कांड में भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, मगर पिछले उदाहरण बताते हैं कि ऐसे मामले सिर्फ ''निपटाने' के लिए ही सीबीआई को सौंपे जाते हैं। यह घटना बिहार ही नहीं देश भर में बालिका गृहों की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। केंद्र को शीघ्र विशेष पहल करते हुए देश भर के बालिका गृहों की निगरानी और सख्त करनी चाहिए।

सत्संग

गुरू

आजकल चारों तरफ गुरू के बारे में बहुत चर्चा होती रहती है। इन दिनों समाज में आपको हर तरह के गुरू देखने को मिल जाएंगे-कंप्यूटर गुरू, मैनेजमेंट गुरू आदि। कह सकते हैं कि आज दुनिया में गुरू शब्द अपना महत्व खो चुका है, क्योंकि समाज में गुरू शब्द का इस्तेमाल हर कहीं किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। गुरू के ''गु' का अर्थ है अंधेरा या अंधकार और ''रू' शब्द का अर्थ है दूर हटाना। यहां अंधकार का आशय (मतलब) अज्ञानता से है। आपकी इसी अज्ञानता का आधार आपकी गलत पहचान है। आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रखी है, जो वास्तव में आप हैं ही नहीं। आम तौर पर इसे पागलपन कहते हैं। इसी तरह खुद को शरीर समझना भी पागलपन है। उदाहरण के लिए अगर आप मानसिक चिकित्सालय में जाएं तो हो सकता है कि आपको बगीचे में एक आदमी खड़ा मिल जाए, जो यह मानता है कि वो एक पेड़ है। हर शाम अस्पताल के कर्मचारियों को उसे भीतर लाना पड़ता है, क्योंकि बिना बुलाए वह अपने आप भीतर नहीं आएगा और सारा समय यूं ही सीधा तना खड़ा रहेगा। लेकिन सुबह जैसे ही अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुलेगा, वह तुरंत भागकर बगीचे में जाकर पेड़ की तरह सीधा तन कर खड़ा हो जाएगा। इसे ही पागलपन कहते हैं, है न? जो आप हैं, उससे अलग हटकर अपने बारे में विास करना ही तो पागलपन है। फ्लिहाल, आप की समस्या भी यही है। आपको लगता है कि आप शरीर हैं। यह सोच भी उतनी बुरी है। आपको लगता है कि आपके विचार ही आप हैं, आपकी सोच ही आप हैं, और आपकी भावनाएं ही आप हैं। आप किसी भी चीज और हर चीज के रूप में खुद की पहचान बना लेते हैं। यही तो अज्ञानता हैं। इस अज्ञानता को जो हटाता है, वही गुरू है। गुरू की मौजूदगी का अनुभव जब आप उसकी मौजूदगी में बैठते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि क्या कहा जाए या क्या सोचा जाए। आप उस वक्त इतने अभिभूत (ओवरवेल्म) होते हैं। आप खुद को एक निरा मूर्ख समझते हैं। अगर ऐसा है, तो यह अच्छी बात है, इसका मतलब है कि चीजें काम कर रही हैं। गुरू की मौजूदगी में अचानक आपकी सारी पहचान आपको बेवकूफी भरी लगने लगती है यानी वे सारी चीजें, जिन पर आपको काफी गर्व होता था और सार्वजनिक (पब्लिक) तौर पर जो आपको महानता का अहसास कराती थीं, अचानक आपको वे सारी चीजें मूर्खता भरी लगने लगती हैं। यह अच्छी बात है।

फोटोग्राफी...

परफेक्ट क्लिक ...जर्मनी के शहर बुकोव में तापमान बढ़ा तो इस लोग स्केरम्यू टजिल झील में आराम करने जा पहुंचे। इस दौरान इस युवक के इस जंप को वहां आए एक टूरिस्ट ने क्लिक कर डाला।

बोफोर्स सौदे

भारत द्वारा स्वीडन से 1987 में खरीदी गई बोफोर्स तोप में दलाली किसने खाई..खाई भी कि नहीं खाई..इस बात को लेकर सीबीआई जांच के बाद भी आज तक इस रहस्य पर से परदा नहीं उठ सका है। लेकिन आमजन में यह धारणा जरूर बन गई कि उस सौदे में कमीशनखोरी हुई थी। बोफोर्स सौदे में कथित दलाली के परसेप्शन के चलते ही 1989 में राजीव गांधी सरकार चली गई थी। उसके सूत्रधार उनकी ही पार्टी के कद्दावर नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो विद्रोह करके अलग हुए थे और बार-बार अपनी जेब में से पर्ची निकाल कर दिखाते थे कि दलाली खाने वालों के नाम उस पर्ची में हैं, और समय आने पर उसे खोलेंगे। लेकिन वो पर्ची कभी नहीं खुली। राजीव गांधी सरकार का पतन कर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए और प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। हैरत यह कि उसके बाद भी बोफोर्स तोप दलाली का खुलासा नहीं हो सका। और वे गुजर भी गए। ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी फ्रांस सरकार से सीधे मोदी सरकार द्वारा खरीदे गए 36 राफेल विमानों में भी कथित घोटाले की बात इस हद तक प्रचारित कर देना चाहती है कि जनता के दिमाग में उसका कीड़ा कुलबुलाने लगे और एक परसेप्शन बन जाए। कहना न होगा कि कांग्रेस अपनी इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाब होते भी दिखने लगी है। आम जन या फिर कहें कि प्रबुद्ध वर्ग ने भी इस सौदे को लेकर आपस में बातचीत शुरू कर दी है। दरअसल, कांग्रेस भी यही चाहती है कि लोग राफेल सौदे को आशंका की नजर से देखें। वह लोगों के मन में शंका के बीच बोना चाहती है। उसकी मंशा यह कदापि नहीं है कि सौदे को लेकर कोई स्पष्ट सफाई राजग सरकार की तरफसे आए। उसका ऐसा कोईइरादा नहीं है। कांग्रेस द्वारा जब-जब राफेल विमानों की कीमतों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, मोदी सरकार यह कहकर बच निकलने का प्रयास कर रही है कि वर्ष 2008 में (यूपीए सरकार) भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच रक्षा सौदों को गोपनीय रखने की संधि हुई थी। इसलिए उस संधि की शतरे और व्यवस्थाओं के तहत राफेल विमानों की कीमत को सामने नहीं लाया जा सकता। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ''खुद मोदी सरकार ने पिछले साल राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में लिखित में राफेल विमान की कीमत तकरीबन 600 करोड़ रुपये बताई थी, तो अब उसकी कीमत बताने से क्यों वह परहेज कर रही है! तब एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा!' कांग्रेस ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए इस सवाल-जवाब की फोटो प्रतिलिपि भी मीडिया को उपलब्ध कराई है। शुरुआती दिनों में राफेल को लेकर जब भी कोई कांग्रेसी सवाल उठाता था तो प्रबुद्धजन उस पर कोई खास तवज्जो देते नहीं दिखते थे। लेकिन अब जब से कांग्रेस ने इस विषय को संवाददाता सम्मेलनों में मथना शुरू किया है, और लोक सभा में सरकार के खिलाफ अविास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने इस डील को लेकर अनेक सवाल भी किए हैं, तब से मीडिया के लोग भी इस पर बहस और जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगे हैं। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि राफेल सौदे में भी अन्ततोगत्वा कथित धांधली के सबूत आने से रहे। इसे मोदी सरकार को समझना होगा और अगर राफेल की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, तो उसके वाजिब कारणों को जनता के समक्ष समय से समय रहते लाना ही होगा वरना 2019 के चुनाव में इसे प्रमुख मुद्दा बनाने के फेर में कांग्रेस तो है ही।

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 352 अंक के उछाल के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई। घरेलु शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हरे निशान पर हुई, जब आज सुबह शेयर बाजार खुला तो उसमें बढ़त देखने को मिली, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत की और कारोबार की समाप्ति पर भी ये हरे निशान पर ही बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स बढ़त बनाते हुए 352.21 अंक यानि 0.95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 37,336.85 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पचास शेयरों वाले निफ्टी पर भी कारोबार की समाप्ति पर बढ़त का असर देखने को मिला और ये हरे निशान पर पहुंचकर 111.05 अंक यानि 0.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,278.35 के स्तर पर बंद हुआ।

गौरतलब है कि कल के कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ हरे निशान पर हुई और कारोबार शुरु होते ही प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। शेयर बाजार में कारोबार की समाप्ति पर भी बढ़त कायम रही और ये हरे निशान पर पहुंचकर बंद हुआ। काराबोर की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 11.28 अंक यानि 0.30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 36,969.51 के स्तर पर खुला और काराबोर की समाप्ति पर ये 126.41 अंक यानि 0.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 36,984.64 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का पचास शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी भी काराबोर की शुरुआत में 34.80 अंक यानि 0.31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,166.80 के स्तर पर खुला और काराबोर की समाप्ति पर ये 35.30 अंक यानि 0.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,167.30 के स्तर पर बंद हुआ।

यमुना सफाई प्राधिकरण बनाने के लिए बातचीत कर रहा नीति आयोग

नयी दिल्ली। सरकार के थिंक-टैंक नीति आयोग ने राजधानी में यमुना नदी की सफाई और कायाकल्प करने के लिये जोर-आजमाइश शुरू कर दी है। आयोग ने कहा कि वह यमुना की सफाई के वास्ते एक प्राधिकरण स्थापित करने के लिये जल संसाधन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि यमुना में 60 से 70 प्रतिशत प्रदूषण और गंदगी अकेले नजफगढ़ नाले से आती है और यदि हम इस एक नाले को ही व्यवस्थित कर पाये तो नदी को फिर से जीवित कर पाना संभंव हो सकता है। कुमार ने तीसरे कलाम अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमने नीति आयोग में यमुना जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित या स्थापित करने का निर्णय लिया है। युमना नदी करीब-करीब खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि हम इस पर नितिन गडकरी के साथ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गडकरी इस तरह के प्राधिकरण के संबंध में तैयार हैं और इस दिशा में जल्द ही परियोजना शुरू होगी।

जल्द बाजार में मिलेगा ऊंटनी का दूध, अमूल इस वर्ष के अंत तक उतारेगा ये मिल्क

अहमदाबाद। अमूल ब्रांड के तहत दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने वाली गुजरात की 18 डेयरियों का महासंघ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इस वर्ष के अंत तक कथित औषधीय गुणों वाले अपने बहुप्रतीक्षित ऊंटनी के दूध को बाजार में उतारेगा। महासंघ के प्रबंध निदेशक आर एस सोढी ने गुरुवार को यूएनआई को बताया कि आधा लीटर की बोतल में इस दूध को सबसे पहले अहमदाबाद में और फिर अन्य स्थानों पर बाजार में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले ऊंटनी के दूध से बने चाकलेट को बाजार में उतारा गया था और उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊंटनी के दूध को बाजार में उतारने के लिए कच्छ जिला दुग्ध उत्पादक संघ यानी सरहद डेयरी के तहत बन रहे संयंत्र की शुरूआत में अभी 3 से 4 माह लग सकते हैं। इससे पहले सरहद डेयरी के चेरयरमैन वलमजी हुंबाल ने एक गुजराती चैनल को बताया था कि ऊंटनी के दूध का व्यावसायिक उत्पादन अगले 3 महिने में शुरू हो जाएगा। इसके संग्रह का काम गत 3 के सितंबर माह से ही हो रहा है और लगभग डेढ़ हजार लीटर दूध प्रतिदिन आणंद में चॉकलेट उत्पादन काम के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के चलते ऊंटनी के दूध की खरीद कीमत पूर्व से लगभग दोगुनी होकर 50 रुपए प्रति लीटर हो गई है और इससे पशुपालकों को फायदा हुआ है। मधुमेह सहित कई रोगों में कथित तौर पर फायदेमंद इस दूध के अपेक्षाकृत जल्दी खराब होने की समस्या होती है और इसको लेकर लंबे विमर्श के बाद वर्ष 2016 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण संबंधी संस्था एफएसएसएआई ने ऊंटनी के दूध को बाजार में उतारने को अनुमति दे दी थी।

अरुण जेटली ने दिए संकेत, सीमेंट-एसी-टीवी पर कम होंगे दाम

नयी दिल्ली (एजेंसी)

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने विश्वास जताया कि राजस्व बढ़ने पर आने वाले समय में सीमेंट, एसी और बड़े टेलीविजन सेट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम होगी और केवल विलासिता और अहितकर उत्पाद ही कर की सबसे ऊंची 28 प्रतिशत की दर के दायरे में रह जाएंगे। जेटली ने आज अपने फेसबुक पृष्ठ पर एक लेख में कहा कि जीएसटी से पहले की कर प्रणाली में घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सामान पर 31 प्रतिशत कर लगता था। उन्होंने उसे 'कांग्रेसी विरासत कर' का नाम दिया।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद पिछले एक साल में 384 सामानों पर कर की दर कम हुई है। केंद्र और राज्य स्तर के कुल 17 करों को मिला कर नया जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जेटली ने कहा, 'आज 28 प्रतिशत की कर श्रेणी को भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इनमें से बचे अधिकांश सामान या तो विलासिता के सामान या अहितकर उत्पाद हैं। इनके अलावा इस श्रेणी में बचे अन्य सामानों में सीमेंट, एसी, बड़े पर्दे के टेलीविजन सेट तथा थोड़े मोड़े अन्य उत्पाद शामिल हैं।'

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आगे राजस्व में और वृद्धि होने पर ये कुछ सामान भी दूसरी श्रेणी में डाले जा सकते हैं। इस प्रकार 13 महीने की रिकॉर्ड अवधि में जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत की श्रेणी को चरणबद्ध तरीके से लगभग समाप्त कर दिया है। यह अब महज थोड़े समय की बात है जबकि 'कांग्रेसी विरासत कर' का मर्सिया पढ़ दिया जाएगा और इसमें सिर्फ लग्जरी और विलासिता के सामान ही बचेंगे।

सेवा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी 68 श्रेणियों में कर की दरें कम हुई हैं। जेटली ने कहा, 'जीएसटी दरें कम करने से सरकार को राजस्व में करीब 70 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। चूंकि राज्य सरकारों को पहले पांच साल के दौरान जीएसटी के पूर्व स्तर से सालाना 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि की गारंटी दी गयी है, इस लिए कर कटौती का पूरा बोझ केंद्र सरकार ने वहन किया है।'

उन्होंने कहा कि घरेलू इस्तेमाल के सभी सामानों पर कर की दरें 28 प्रतिशत से कम कर 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत कर दी गयी हैं। जेटली ने कहा कि सीमेंट छोड़ निर्माण कार्य में काम आने वाले अन्य सभी सामानों पर दरें कम हुई हैं। बिजली से चलने वाले अधिकांश घरेलू सामानों पर भी दरें कम हुई हैं। खरीदारों को जीएसटी

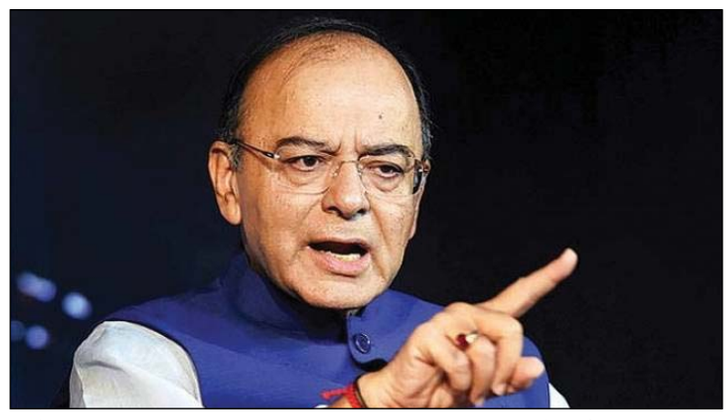

से तैयार इस वातावरण से अच्छा खरीदारी का अवसर पहले कभी नहीं था। यह आजादी के बाद सबसे बड़ा कर-सुधार का जश्न मनाने का मौका है जिससे 'कांग्रेसी विरासत कर' की जगह 'गुड एंड सिम्पल टैक्स (एक अच्छा और सरल कर)' आ गया है। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद की पिछले सप्ताह हुई बैठक में 88 तरह के उत्पादों पर कर कम करने का निर्णय किया गया। यह कटौती आज से प्रभावी हुई है।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं का नामांकन दर सबसे कम: सर्वेक्षण

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं का नामांकन दर सबसे कम है, इसके बाद राज्यों के निजी मुक्त विश्वविद्यालय और सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालयों का स्थान आता है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) में यह बात सामने आई है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 25.8 प्रतिशत है जिसका आकलन 18 से 23 आयु वर्ग के छात्रों के संदर्भ में होता है। साल 2017-18 की एआईएसएचई रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी कम है, इसके बाद राज्यों के निजी मुक्त विश्वविद्यालयों का आता है और फिर सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालय का आता है जहां छात्राओं का नामांकन कम है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.66 करोड़ है जिसमें 1.92 करोड़ लड़के और 1.74 करोड़ छात्राएं हैं। कुल नामांकन में लड़कियों की हिस्सेदारी 47.6 प्रतिशत है। वहीं, पुरूष आबादी के लिये सकल नामांकन दर (जीईआर) 26.3 प्रतिशत और महिला आबादी के लिये जीईआर 25.4 प्रतिशत है। अनुसूचिज जातियों के लिये यह 21.8 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिये यह 15.9 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2017 में अधिक पुरूषों को पीएचडी प्रदान किया गया और इनमें से ज्यादातर विज्ञान संकाय में थे।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में 34000 छात्रों को पीएचडी स्तर की डिग्री प्रदान की गई। इनमें 20,179 पुरूष और 14,221 महिलाएं शामिल हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर ज्यादा छात्रों ने सामाजिक विज्ञान में दाखिला लिया और इसके बाद प्रबंधन संकाय का स्थान सामने आया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 46,114 विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया।

सरकार ने गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने के आदेश को अधिसूचित किया

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सरकार ने चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस या बी - श्रेणी के शीरा (बी- मोलासेस) से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है। इससे चीनी मिलों को चीनी अधिशेष वाले इस वर्ष में राहत मिलेगी। इस संबंध में गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 को संशोधित किया गया है और इसे केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस कदम से अधिशेष वर्षों में (जब गन्ने का अधिक उत्पादन होगा) मिलों को सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल का निर्माण करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने अधिसूचना में कहा, ÷जब एक चीनी मिल सीधे गन्ने के रस या बी - शीरे से एथेनॉल उत्पादित करती है, तो ऐसे कारखानों के मामले में वसूली दर (रिकवरी रेट) को हर 600 लीटर के मामले में एक टन चीनी के उत्पादन के बराबर माना जायेगा। अभी तक चीनी मिलों को निम्म श्रेणी के शीरे (सी - मोलासेस) से एथेनॉल बनाने की अनुमति थी।

गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद यह शीरा बचता है। मोलासेस का उपयोग स्प्रिट और एल्कोहल समेत अन्य उत्पादों को बनाने में होता है। पिछले महीने सरकार ने पहली बार बी श्रेणी के शीरे से उत्पादित एथेनॉल का भी मूल्य तय किया और दिसंबर 2018 से शुरू हो रहे नये सत्र के लिये इसका दाम 47.49 रुपये प्रति लीटर रखा है। निम्न श्रेणी के शीरे (सी - मोलासेस) से उत्पादित एथेनॉल का भाव 2.85 रुपये बढ़ाकर 43.70 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

देश में पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने को अनिवार्य किया गया है लेकिन पर्याप्त मात्रा में एथनॉल की मौजूदगी नहीं होने से यह 4 प्रतिशत पर सिमट कर रह गया है। एथनॉल की ऊंची कीमत से चीनी मिलें अधिक एथनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित होंगी। चीनी मिलों ने दिसंबर 2018 से शुरू होने वाले विपणन वर्ष के दैरान तेल मार्केटिंग कंपनियों को 158 करोड़ लीटर एथनॉल की आपूर्ति करने का अनुबंध किया है। इससे पिछले वर्ष 78.6 करोड़ लीटर एथनॉल की आपूर्ति की गई थी।

अगस्त में ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता है भारतीय रिजर्व बैंक: एचडीएफसी बैंक

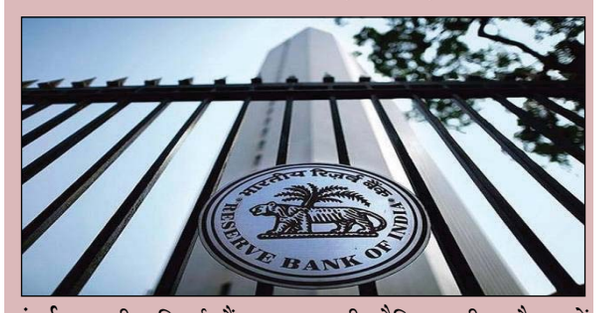

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक अगस्त की मौद्रिक समीक्षा बैठक में ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता है। एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। एचडीएफसी बैंक के अर्थशास्त्रियों ने एक नोट में कहा, 'यह एक नजदीकी और कड़ाई से संतुलन बैठाने का मामला होगा। लेकिन हमारा अनुमान है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला लेगा।'

केंद्रीय बैंक की जून की मौद्रिक समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में चौथाई प्रतिशत की वृद्धि की थी। उसके बाद आए आंकड़ों में मुद्रास्फीति बढ़ी है। पिछले सप्ताह देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भी कहा था कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में संभवत- बदलाव नहीं करेगा।

एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति का जोखिम अभी कायम है। हालांकि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ऐतिहासिक रुख से कम रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक अभी इंतजार करेगा और बारिश का वितरण देखेगा। चावल और गेहूं के अलावा अन्य वस्तुओं की खरीद आगे का रुख तय करेगी।

डीबीटी प्रणाली के तहत हैं 500 से अधिक योजनाएं: अमिताभ कांत

नयी दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज कहा कि 500 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ

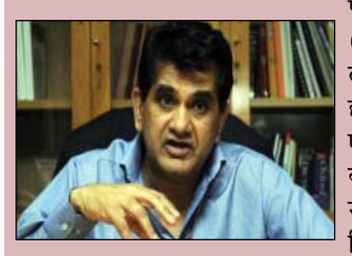

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) व्यवस्था के तहत लाभार्थियों के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जा रहा है। एक कार्यक्रम में अमिताभ कांत ने कहा कि कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पुराने नियमों को खत्म किया है। उन्होंने देश में जनसांख्यिकीय लाभांश तथा समावेशी वृद्धि के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ समावेशी होने पर ही वृद्धि टिकाऊ हो सकती है। वह केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा आयोजित व्याख्यान ' ट्रांसफोर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स- अ न्यू इंडिया बाय 2022' में बोल रहे थे।

डाटा लीक पर पेटीएम की सफाई, कहा- अपने यूजर्स की जानकारी निवेशकों से नहीं की साझा

नई दिल्ली।

फेसबुक के यूजर के डाटा लीक प्रकरण पर मचे बवाल के बीच डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम पर ऐसा ही कुछ आरोप लगा है। हालांकि कंपनी ने सफाई दी है कि वह अपने प्रयोगकर्ताओं या यूजर्स का डाटा कभी अपने निवेशकों या किसी अन्य विदेशी इकाई से साझा नहीं करती है। पेटीएम ने कहा कि वह डाटा को स्थानीय स्तर पर भारत में स्टोर करती है, जिस पर किसी बाहरी पक्ष की पहुंच नहीं होती। वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पास पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व है। यह देश की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान कंपनी है। कंपनी ने कहा कि वह अपने यूजर्स के डाटा को कभी तीसरे पक्ष की एजेंसियो, अंशधारकों, निवेशकों या विदेशी इकाई से साझा नहीं करती है। सांसद नरेंद्र जाधव ने राज्यसभा में कहा था कि चीन की अलीबाबा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अलीबाबा के पास पेटीएम की हिस्सेदारी है। इसके बाद ही बवाल मचा। राज्यसभा में सवाल उठने के बाद पेटीएम के प्रवक्ता ने ई-मेल से भेजे जवाब में कहा कि यह एक भारतीय के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है। हम अपने यूजर्स के डाटा को अपने किसी निवेशक या विदेशी इकाई से साझा नहीं करते हैं। पेटीएम ने नोएडा में 10 एकड़ जमीन खरीदी है। कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप के मामले में इसे सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। कंपनी के कारोबार में विस्तार हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह सौदा 150 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। कंपनी जमीन सीधे नोएडा अथॉरिटी से खरीद रही है इसलिए उसे शायद इससे कुछ कम कीमत चुकानी पड़ेगी।

सूरत। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरुओ की पूजा अर्चना करते गुरुकुल के बालक गुरुकुल वेड रोड़।

२६ हजार से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल में शामिल होंगे

एनएमसी बिल के विरोध में राज्य के डॉक्टर हड़ताल पर

अहमदाबाद। चिकित्सा सेवा और शिक्षा पर भंग के समान डेमोक्रेटिक विरोधी और गरीब विरोधी ऐसा विवादित नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल -२०१७ के विरोध में शनिवार को गुज रातभर के डॉक्टर हड़ताल पर जायेंगे । जिसके कारण सुबह में ६ बजे से लेकर शाम के ६ बजे तक राज्य के सभी अस्पताल, लेबोरेटरी में सेवा ठप हो जाएगी। हालांकि इमरजन्सी सेवाएं चालु रहेगी । केन्द्र सरकार के विवादित एनएमसी बिल के विरोध में गुजरात सहित देशभर के पोने तीन लाख से ज्यादा डॉक्टर शनिवार से हड़ताल में शामिल होकर अपना विरोध व्यक्त करेंगे । एनएमसी बिल गैर ज नतंत्र, गरीब विद्यार्थियों को नुकसानकर्ता और चिकित्सा सेवा और शिक्षा के अस्तित्व पर खतरे के समान होने से केन्द्र सरकार ने तुरंत इसे वापस लेने की मांग आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, गुजरात राज्य ब्रांच के प्रमुख डॉ. भूपेन्द्र शाह और माननीय मंत्री डॉ. कमलेश सैनी ने बताया है।

उन्होंने आगे बताया है कि, केन्द्र के विवादित एनएमसी बिल को लेकर कुछ समय पहले ही शहर में आईएमए की २१९वीं कारोबारी समिति की महत्व की बैठक आयोजित की गई थी और शनिवार को भी आईएमए, गुजरात राज्य ब्रांच की एक्शन कमिटी की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें यह बिल को प्रस्तावित संशोधन के बाद भी अमीरों के पक्ष में बताया गया । एनएमसी बिल के कारण एक तरफ गरीबों और वंचित वर्ग के लिए चिकित्सा शिक्षा असंभव हो जाएगी और दूसरी तरफ समाज के सिर्फ अमीर और संपन्न वर्ग के लोग ही डॉक्टर्स बन सकेंगे, यह मामले को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा । हाल में अधिकतर राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से फीस निश्चित करती समिति की रचना की गई है । इसकी वजह से अधिकतर राज्यों में राज्य सरकारों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ५० फीसदी कोटा है । यह सरकारों द्वारा मेरिट के आधार पर पसंद किए गए विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कॉलेज जितनी फीस चुकाते हैं। मेडिकल में गरीब और ज रूरतमंद विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका है लेकिन एनएमसी बिल के द्वारा केन्द्र सरकार यह सभी बदलना चाहती है।

सड़े हुए आलू, चने, प्रदुषित पानी मिलने से सनसनी

राजकोट-सुरत में पानीपुरी के विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई

सूरत। एस.एम.सी का एक अधिकारी रोड़ किनारे लारी लगा कर पानीपुरी बेचने वालों की क्वालिटी चैकिंग करता हुआ।

सूरत। मसालेदार पानीपुरी खाने के शौकिन लोगों को सावधान हो जाने की जरुरत है । आज बडौदा, राजकोट समेत बहुत से इलाकों में पानीपुरी की लारी चलानेवाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई । राजकोट में पानीपुरी विक्रेताओं पर आरोग्य विभाग की ओर से छापेमारी की गई। मिली जानकारी के मुताबिक राजकोट शहर के भक्तिनगर, सांगणवा चोक, रेसकोर्स समेत के इलाको में पानीपुरी की लारी वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और चेकींग की गई। इस दौरान १५० किलो से अधिक अखाद्य पदार्थों का नाश किया गया है। इसी तरह बडौदा में भी कार्रवाई की गई है। गंदगीवाले इलाको में कार्रवाई की गई और छापेमारी की गई। बडौदा में चार हजार किलो पानीपुरी का नाश किया गया है और युनिटो के खिलाफ कार्रवाई की गई है । अखाद्य तेल में से बनाई गई पानीपुरी, अखाद्य तेल, सड़े हुए आलु, सड़े हुए चने, दुषित पानी से बनी हुई पानीपुरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह सभी चीजों को कार्रवाई के दौरान नष्ट कर दिया गया।

बडौदा शहर में पानीपुरी गंदगी से ग्रस्त दिख रही है । पानीपुरी शहर के लोगों को खूब पसंद भी है किन्तु सामान्य लोग गंदगी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे है। पानीपुरी की लारियां शहर के अलग अलग इलाको में सरलता से देखी जा सकती है। सभी ज गह लोग बड़े चाव से पहुंच रहे है किन्तु गंदगी की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जानकार लोगों ने बताया है कि पानीपुरी खाने के शौकीन लोगों को यदी वास्तविकता की जानकारी मिल जाए तो पानीपुरी कभी भी नहीं खायेंगे। खाने की बात तो दुर रही पास भी नहीं जाएंगे । गंदगी से ग्रस्त विस्तारो में पानीपुरी बनाई जा रही है। एक और मोनसून की सिजन चल रही है तब पानीपुरी के कारण भी अलग अलग रोग होने की दहेशत दिख रही है। रोगों को रोकने के लिए आरोग्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है । इसके चलते आज पानीपुरी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच भी की गई । बडौदा के हुजरात पागा, हाथीखाना, तुलसीवाडी, समा, छाणी गाम, खोडीयानगर, नवायार्ड, नरसिंह टेकरी, सुदामा नगर, तुलसी की चाली सहित के इलाकों में कार्रवाई की गई। ५० से भी अधिक पानीपुरी बनानेवाले युनिटो के खिलाफ कार्रवाई की गई । छापेमारी की कार्रवाई से पानीपुरी विक्रेताओं में दहेशत फैल गई है।

गुजरात : तापमान.....

अहमदाबाद।

अहमदाबाद समेत कहां-कितना तापमान रहा वह निम्न है।

स्थल	तापमान
अहमदाबाद	३१.१
डिसा	३०.२
गांधीनगर	-
ईडर	२८
वीवीनगर	-
बडौदा	३०.४
सुरत	२९.६
वलसाड	२८.९
अमरेली	३२
भावनगर	३३.५
द्वारका	३०.५
ओखा	३१.२
पोरबंदर	३०.६
राजकोट	३२.८
वेरावल	२९.४
दिव	३१
सुरेन्द्रनगर	३२.५
भुज	३३
नलिया	३१.८
कंडला एयरपोर्ट	३४.४
कंडला पोर्ट	३३.६
महुवा	२९.४

आठवे दिन ट्रक हडताल आखिर समाप्त हुई

ट्रक हडताल : उद्योगो को हजारो करोड़ का नुकसान

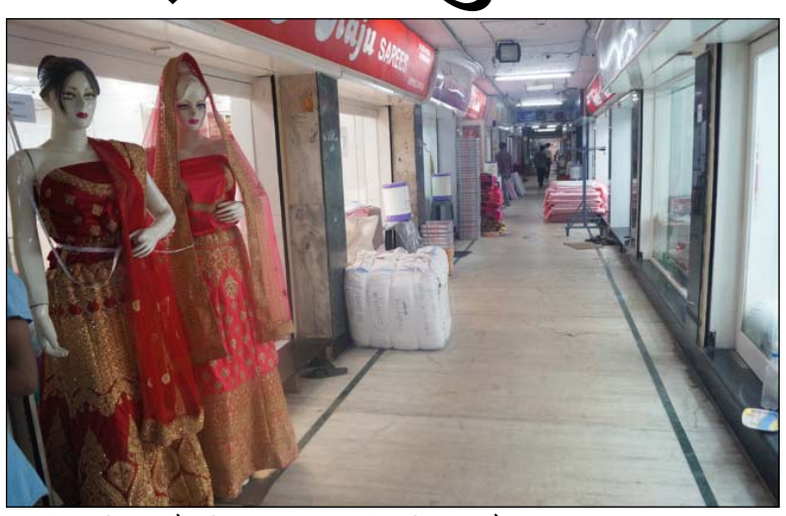

सूरत। पिछले आठ दिन से जारी ट्रक हडताल आखिरकार समाप्त हो गई है। दिल्ली में मिटींग के बाद इस मामले में घोषणा की गई । पिछले दिनों से जारी ट्रक हडताल के चलते उद्योगो का हजारो करोड़ों का नुकसान हो चुका है । ओल इंडिया मोटर्स ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस की जारी ट्रक हडताल के चलते मुश्किले दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। पिछले आठ दिनों से देशभर में ट्रक हडताल चल रही थी जिसके चलते गुजरात के उद्योगो को १५ हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। हडताल के चलते जरुरी चीजवस्तुए फैक्ट्री तक नहीं पहुंच रही थी। परिवहन सुविधा नहीं होने के चलते मुश्किले आ रही थी। गुजरात के केमिकल, टेक्सटाइल, सिरामीक और फार्मा उद्योग में चीजवस्तुएं भर गई है। एक जगह से दुसरी जगह इन चीजों को ले जाने में अडचण आ रही थी। चीजवस्तओं का भंडार हो गया है। रो-मटीरीयल नहीं आने से उत्पादन भी असर पडा है।

कन्टेनर नहीं चलने से उत्पादित चीजवस्तुएं एक जगह पर इकठ्ठा हो चुकी है। देश के ग्रोथ इंजन के रुप में जाने जानेवाले गुजरात को ट्रक हडताल के चलते पिछले छह दिनों के दौरान ही १५ हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है।

गुजरात चेम्बर ओफ कॉमर्स एन्ड इन्डस्ट्री के प्रमुख का कहना है कि ट्रक हडताल के चलते जरुरी चीजवस्तुएं फैक्ट्री तक नहीं पहुंच रही है। जिसके कारण बहुत सी परेशानिया आ रही है। केमिकल, टेक्सटाइल और सिरामीक के हब के रुप में गुजरात को जाना जाता है।

बच्ची के अपहरण केस में नाटकीय मोड़

माता एक महीने की बच्ची को नाले में छोड़कर आयी

अहमदाबाद । गोता के प्रार्थना लेविस फ्लेट के बाहर से एक महीने की बच्ची को उठाकर ले जाने के मामले में अब पुलिस जांच में चौंकानेवाला नाटकीय मोड़ सामने आया है । पुलिस की जांच में बच्ची की माता इसे चांदलोडिया ब्रिज के नीचे स्थित रेलवे ट्रेक के पास छोटे नाले में छोड़कर आयी थी । घर आकर उसने अपनी सास को बताया कि बाइक पर आये दो शख्स बच्ची को लेकर फरार हो गये । सवा घंटे तक एक महीने की बच्ची छोटे नाले में पड़ी रही। हालांकि कुत्ता या प्राणी उठाकर नहीं ले गये और इसे अन्य नुकसान नहीं होने पर पुलिस के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों ने राहत महसूस किया है। फिलहाल तो बच्ची को उपचार के लिए सोला सीविल अस्पताल में भर्ती करायी गई है।

इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, गोता न्यू एसजी रोड पर स्थित प्रार्थना लेविस फ्लेट में रहते कृणालसींग की एक एक महीने की बच्ची यक्षिता को गत शाम को ८ बजे के करीब फ्लेट के बाहर से बाइक पर आये दो शख्स उनकी पत्नी पुष्पा के हाथ से उठाकर फरार होने की जानकारी पुलिस कंट्रोलरुम को मैसेज मिला था । पुलिस को जानकारी मिलने पर पूरे शहर में नाकाबंदी की गई थी। सोला, चांदखेडा और साबरमती पुलिस की सीमा के निकट होने से तीन पुलिस स्टेशन का काफिला घटना स्थल पर पहुंच गया था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फूटेज आदि लेकर जांच शुरू की थी। साबरमती पुलिस ने बच्ची की माता पुष्पाबहन की पूछताछ शुरू की। पुलिस ने पुष्पाबहन की फिर से जांच करने पर वह निराश हो गई थी और अपनी एक महिने की बच्ची को चांदलोडिया ब्रिज के नीचे स्थित रेलवे ट्रेक के पास छोटे नाले में छोड़कर आयी होने का पुलिस को बताया। जिसकी वजह से पुलिस ने तुरंत चांदलोडिया ब्रिज के नीचे नाले में पहुंच गई।

पुलिस ने छारानगर में लोगों के घर में घुसकर पीटा

छारानगर में पुलिस पर हमला PSI सहित के कर्मी घायल

अहमदाबाद । शहर के कुबेरनगर क्षेत्र में स्थित छारानगर में देर रात को चल रहे शराब के अड्डे को बंद कराने के लिए गई पुलिस सरदारनगर पुलिस स्टेशन के डी-स्टाफ पीएसआई सहित अन्य पुलिसकर्मी पर कई असामाजिक तत्वों ने हमला कर देने से माहोल तनावपूर्ण हो गया था और एक समय तो पुलिस और पब्लिक के बीच मारपीट के दृश्य सामने आ गये।

पुलिस के कर्मचारियों ने लोगों के घर में घुसकर पिटाई करने का गंभीर आरोप लगने पर फिर एकबार पाटीदार आंदोलन के समय में जिस प्रकार से पुलिस ने पाटीदारों पर अत्याचार किया था ऐसा ही चित्र सामने आने पर पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह पूरे मामले में पुलिस ने ३५ शख्सों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी । पुलिस अत्याचार का शिकार हुए स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ५० से ज्यादा गाड़ी तथा वाहनों की तोड़फोड़ की और लोगों के घर में घुसकर महिला सहित लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इस घटना में कई वकीलों तथा प्रेस फोटोग्राफर भी पुलिस अत्याचार का शिकार बने होने की बात जानकारी सामने आयी थी।

सुबह में पांच बजे तक चले पुलिस के कोम्बिग बाद छारानगर तथा कुबेरनगर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया छारानगर में पुलिस अत्याचार मामले में शुक्रवार को सुबह में छारा समाज के लोगों ने पुलिस के काम के विरूद्ध सख्त विरोध किया गया था और बड़ी संख्या में भीड़ पुलिस स्टेशन में पहुंच गई, जहां पुलिस के विरूद्ध भारी नारेबाजी की गई।

गंदगी मामले में कार्रवाई २१४ युनिट सील की गई

अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर के अलग अलग इलाकों में गंदगी करके शहर को प्रदुषित और गंदा करने की प्रवृत्ति करनेवाले युनिटो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आज भी जारी रही। जिसके चलते अलग अलग इलाको में कार्रवाई की गई। सबसे अधिक नये पश्चिम जोन में ६५ युनिट सील की गई। म्युनिसिपल कमिशनर विजय नेहरा ने सार्वजनिक में गंदगी करने वाले इकाई के विरूद्ध सख्ती से काम लेने की संबंधित जोन के हेल्थ विभाग को आदेश दिया गया है, जिसकी वजह से गत दिन दक्षिण जोन, तो शुक्रवार को दक्षिण जोन, पूर्व जोन, मध्य जोन, पश्चिम जोन और नये पश्चिम जोन में प्रशासन ने कार्रवाई की है। हेल्थ विभाग की टीम ने शुक्रवार को विशेष तो पश्चिम जोन और नये पश्चिम जोन में कार्रवाई करके नवरंगपुरा, नारणपुरा, आंबावाडी सहित शहर के कई क्षेत्रों में गंदगी फैला रहे कुल १६५ से ज्यादा इकाई को सील किया गया। इतना ही नहीं हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने देर रात को छापेमारी कर दोषी कई इकाई के पास से ६० हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया । पिछले दो दिन से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ विभाग के यह कामकाज से सार्वजनिक स्थलों में गंदगी और कचरे डालकर प्रदूषण फैला रहे इकाई में दहशत की भावना फैल चुकी है। सार्वजनिक स्थलों पर कचरे डालनेवाले इकाई को सील लगाने की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अभियान के तहत गत दिन देर रात को १२ बजे पश्चिम जोन की हेल्थ विभाग की टीम नारणपुरा वोर्ड और नवरंगपुरा वोर्ड में पहुंची थी। नारणपुरा वोर्ड के अंकुर चार रास्ते पर अपोलो फार्मसी, बिजी पान पार्लर, सत्यम फूटवेर, रमी फूटलर्स, नवरंगपुरा वोर्ड में स्थित म्युनिसिपल मार्केट की हेवमोर, आईस्क्रीम, वाह फूड तथा आंबावाडी सर्कल की ओम ब्रे (फूड), संघवी ब्रधर्स, फ्रेन्ड पान पार्लर को गंदगी फैलाने के मामले में सील किया गया।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com